districts of Panchmahal, Surat, Rajkot, Bharuch, Junagadh, Amreli, Kheda and Banaskantha of Gujarat in the current financial year;

(b) if so, the details of allocations of admissions of each standards; and

(c) what are the number of Kendriya Vidyalayas functioning in each district in Gujarat ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There are 40 Kendriya Vidyalayas at present functioning in Gujarat. There is no system of allocating or opening of Kendriya Vidyalayas on a district-wise or State-wise basis.

देश में बालविकास केन्द्र

3361. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार तथा जिला-वार कितने बाल विकास केन्द्र कार्यरत हैं और इनकी स्थापना कब से हुई है;

(ख) गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित केन्द्रों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) इन केन्द्रों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की जाती है;

(घ) क्या सरकार नये बाल विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासव राजेश्वरी) : (क) वर्ष 1975-76 में समेकित बाल विकास सेवा योजना के आरम्भ होने से 31-3-1993 तक देश में कुल 3066 आई सी डी एस परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें राज्य क्षेत्र की 195 परियोजनाएं भी शामिल हैं । इन आई सी डी एस परियोजनाओं की राज्य वार और जिला-वार संख्या अनुपत्र में दी गई है । [देखिए परिशिष्ट 169, अनुपत्र संख्या 68]

(ख) 46 आई सी डी एस परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 2595 आंगनवाड़ियों में गैर सरकारी संगठन समेकित बाल विकास सेवा योजना चला रहे हैं । गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही आई सी डी एस परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है । शेष आई सी डी एस परियोजनाएं सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही हैं ।

(ग) योजना के मापदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आई सी डी एस परियोजना को चालू रखने हेतु एक वर्ष में औसतन 14.56 लाख रुपए दिए जाते हैं । यह राशि सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पूरक पोषाहार के अतिरिक्त होती है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान 14 राज्यों में 200 नई आई सी डी एस परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है । चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित आई सी डी एस परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई

विवरण 1

गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं/आंगनवाड़ियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	परियोजनाओं की संख्या	आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	100
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	27	338
4.	बिहार	0	0
5.	गोआ	0	0
6.	गुजरात	7	1527
7.	हरियाणा	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	4	0
10.	कर्नाटक	0	0
11.	केरल	0	0
12.	मध्य प्रदेश	4	363
13.	महाराष्ट्र	0	0
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	0	0
16.	मिजोरम	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0
18.	उड़ीसा	1	34
19.	पंजाब	0	0
20.	राजस्थान	1	113
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0
23.	त्रिपुरा	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	1	120
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0
28.	दादर और नगर हवेली	0	0
29.	दमन और दीव	0	0
30.	दिल्ली	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0
	जोड़	46	2595

विवरण–2

वर्ष 1993-94 के लिए 200 केन्द्रीय प्रायोजित आई सी डी एस परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1.	असम	7
2.	गुजरात	11
3.	हरियाणा	3
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	जम्मू एण्ड कश्मीर	1
6.	कर्नाटक	18
7.	केरल	9
8.	महाराष्ट्र	30
9.	मणिपुर	1
10.	पंजाब	3
11.	राजस्थान	17
12.	उत्तर प्रदेश	69
13.	पश्चिम बंगाल	29
14.	तमिलनाडु	1
	जोड़ :	200

LITERACY TARGET IN RAJASTHAN

3362. SHRI RAJENDRA PRASAD MODY : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have set the target to attain 85 per cent literacy status by the year 2018 and 100 per cent literacy by the year 2027;

(b) whether it is also a fact that Rajasthan will not be able to achieve even 85 per cent literacy by 2030; and

(c) if so, what action Government are taking to achieve these targets in Rajasthan and the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM

3363. SHRI RAJENDRA PRASAD MODY : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government propose to review the national education system in the country;

(b) whether the present system of education has little relevance to the productivity and national development; and